

भजनलाल पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए

बिहार/जयपुर, 20 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री एवं अन्य सदस्यों को मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार के निर्माण में संकल्पित होकर कार्य करेगी तथा बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचन्द बैरवा तथा विधायक कुलदीप धनखड़ सहित, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चित्र में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मंच पर उपस्थित थे।

डॉ. उमर उन नबी धुरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैंडलर्स से टेलीग्राम पर आए निर्देशों के अनुसार, बम बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने नैटवर्क के स्टॉक में अमोनियम नाइट्रेट, जो एक शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री है, को कई जगह जमा कर रखा था। अधिकारियों ने फरीदाबाद में लगभग 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, टाइमर और अन्य सामग्री बरामद करने का दावा किया है।

जांच में मिली सीसीटीवी फुटेज से एक सुराग मिला है: हंडई आई-20 को दिल्ली ले जाने से पहले अल-फलाह मैडिकल कॉलेज के परिसर में 11 दिनों तक पार्क किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद उमर ने, शायद अपने साथियों की गिरफ्तारी और उस पर बढ़ते दबाव में हताश होकर यह हमला करने का फैसला लिया। एक अधिकारी के अनुसार, “उसने यह सब प्लान किया और अपने दोस्तों के अर्रेस्ट होने के बाद इसे अंजाम दे दिया।

एन.आई.ए. और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक रूप से उमर उन-नबी को रेड फोर्ट ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध बताया है और इस घटना को

आतंकी हमला घोषित किया है। हालांकि कई महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि उन पर किस स्तर तक नियंत्रण था, जे.ई.एम. हैंडलर्स से उन्हें कितना सीधा निर्देश मिला और क्या वे वास्तव में आत्मघाती हमलावर थे, अब भी जांच के दायरे में हैं।

जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि जिस डिवाइस में धमाका हुआ, वह संभवतः उन्हीं सामग्रियों से बनाया गया था, जो फरीदाबाद से बरामद हुई थीं। इससे एक जुड़े हुए टैरर नेटवर्क की कड़ियां और मजबूत होती हैं। अभी सुरक्षा एजेंसियां मॉड्यूल की फंडिंग, उसके ऑपरेशन की पहुंच और पूरी लॉजिस्टिक श्रृंखला की जांच कर रही हैं। एक अधिकारी के अनुसार, “यह घटना उसी घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिससे एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ।”

अगर आरोप प्रमाणित होते हैं, तो उमर का मामला भारत के पेशेवर डॉक्टर वर्ग में कट्टरपंथी होने के सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक होगा। एक कथित टैरर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में मैडिकल प्रैक्टिशनर्स का शामिल होना इस बारे में बड़े मुश्किल सवाल खड़े

करता है कि कैसे एक्स्ट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बहुत पढ़े लिखे, दिखने में सर्विस ओरिएन्टेड कम्युनिटीज में घुस सकती है। नई दिल्ली की एजेंसियों के सामने चुनौती न सिर्फ अदालत में टिकने वाला मजबूत मामला बनाने की है, बल्कि उन्हें यह भी तय करना है कि भविष्य में ऐसे वाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल को कैसे पहचाना और रोका जाए। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर हैं कि जांचकर्ता डॉ. उमर उन-नबी की पूरी कहानी को कैसे जोड़ते हैं।

‘पढ़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजु ने कहा कि अब डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में दिखाये। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए भी दिखाया गया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीतीश कुमार के पारंपरिक समर्थन का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश रणनीति इसी जनसांख्यिकी (डैमोग्राफी) पर टिकी हुई है। यूपी में कुर्मी वोटरों की संख्या बिहार की तुलना में लगभग दोगुनी है, और कई जिलों में यह समुदाय, दूसरे ओबीसी और ईबीसी समुदायों के साथ, पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है।

अब भगवा पार्टी का मकसद यही है कि बिहार वाले जातीय संतुलन और अभीष्ट पहुंच (टांगेंटेड आउटरीच) को यूपी में दोहराकर इस वोट आधार में संघ लगाई जाए। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व यूपी में एक ताकतवर ओबीसी चेहरे को संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप

पंजाब पुलिस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को अंजाम दे सकते थे। पंजाब पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के दो आतंकवादियों का

‘हमारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीडिया संस्थान को दबाने की कोशिश बताया। संपादक प्रबोध जमवाल और अनुराधा भसीन ने सोशल मीडिया पर जारी किये गये एक संयुक्त बयान में कहा कि “जम्मू कार्यालय पर छापे और हमारे खिलाफ निराधार आरोप एक बार फिर हमें चुप कराने की कोशिश है।”

उन्होंने कहा कि 1954 में वेद भसीन द्वारा स्थापित कश्मीर टाइम्स ने हमेशा स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखा है। “हमने इस क्षेत्र की सफलताओं और विफलताओं दोनों को समान मेहनत से दर्ज किया है। हमने उन समुदायों को आवाज दी है, जिनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। जब दूसरे चुप रहे, तब हमने कठिन सवाल पूछे।”

संपादकों ने कहा कि भले ही 2021-22 में “लगातार एवं निर्मम रूप से निशाना बनाए जाने” के बाद, अखबार का प्रिंट संस्करण बंद कर दिया गया था, लेकिन कश्मीर टाइम्स अब भी डिजिटल रूप से काम कर रहा है और उसका सारा काम उसकी वेबसाइट पर सबके लिये उपलब्ध है।

संपादकों ने कहा कि भले ही 2021-22 में “लगातार एवं निर्मम रूप से निशाना बनाए जाने” के बाद, अखबार का प्रिंट संस्करण बंद कर दिया गया था, लेकिन कश्मीर टाइम्स अब भी डिजिटल रूप से काम कर रहा है और उसका सारा काम उसकी वेबसाइट पर सबके लिये उपलब्ध है।

में आगे लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस संभावना को इन रिपोर्टों से और बल मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूदा यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

भाजपा के लिए बिहार से मिली सीख स्पष्ट है: जातीय गणित, खासकर कुर्मी और व्यापक ओबीसी समर्थन की एकजुटता राजनीतिक परिणामों को पूरी तरह बदल सकती है। जैसे-जैसे 2027 के यूपी चुनाव की उलटी गिनती शुरू होती है, पार्टी अपने “बिहार में खरे उतरें” फ़ॉर्मूले को यूपी में लागू करके एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही है, जो उसे एक निर्णायक जनदेश दिला सके।

एनकाउंटर किया गया है जिसमें दो आतंकी घायल हैं। घायल हुए आतंकियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

प. बंगाल में वामपंथी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नंदीग्राम में कार फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ उग्र आंदोलन करके उस जमे हुए सिस्टम को हिला दिया था।

जब वे सत्ता में आईं उन्हें पता था कि सिस्टम को कैसे मोड़ना है और गलत मतदाता सूचियों व वोटिंग में हेराफेरी के ज़रिये चुनावी जीत कैसे हासिल करनी है। अपने पहले कार्यकाल और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगे तगड़े झटके के बाद, उन्होंने एक ऐसा संरक्षण तंत्र खड़ा किया, जो पूरे बंगाल के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में फैला हुआ है।

तृणमूल के ज़मीनी कार्यकर्ता आसानी से पहचाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनका पूरा विवरण मिल जाता है। वे अक्सर बहुत पतली सोने की चेन और दाढ़िने हाथ में वैंसा ही सोने का ब्रेसलैट पहनते हैं। बीच के स्तर के नेताओं के पास कई नई एसयूवी हैं और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के पास चमचमाती मोटरबाइकें।

वे तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं और अक्सर मामूली सी बात पर भी अपनी कार से आम लोगों पर हमला कर देते हैं। हाल में न्यू टाउन इलाके में कार लेकर जा रहे आम लोगों पर, कार का स्पर्श करते हुये गुजरने पर भी, इसी तरह के हमले हुए, यहाँ तक कि उन लोगों

को उनके अपने गेटेड परिसर के अंदर तक पीटा गया। कई मायनों में, आम लोग, जो सत्ता पक्ष से जुड़े नहीं हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। यही लोग बूथ पर कब्जा करते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और, आम तौर से, यह सुनिश्चित करते हैं कि विपक्ष के पक्ष में वोट पड़ ही न सके। नतीजतन, तृणमूल उम्मीदवार अक्सर रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। उदाहरण के लिए, ममता बनर्जी के मशहूर भतीजे ने देश में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। बंगाल में लोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से वोट डाल ही नहीं पाते, क्योंकि हर जगह तृणमूल के गुंडों का खतरा रहता है।

इसके अलावा, मृतक मतदाता सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी मदद हैं। ऐसे मृत मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर कई अनौपचारिक अनुमान और आँकड़े सामने आते रहते हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि लगभग 40 लाख मृत लोगों के नाम अभी भी जीवित मतदाता सूची में मौजूद हैं।

साथ ही, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं। पहले लैपट फ्रंट के शासनकाल में इन्हें राज्य में घुसने में मदद दी जाती थी। तब ममता खुद इन अवैध प्रवासियों की कड़ी विरोधी थीं और संसद में यह मुद्दा कई बार उठाया था।

‘राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधानसभा से पारित विधेयक नहीं रोक सकते’

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक फैसले में गुरुवार को कहा कि राज्य के राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों को मंजूरी देने या न देने के लिए जरूरी समयसीमा तय नहीं कर सकता लेकिन राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी भी विधेयक को नहीं रोक सकते। हालांकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि लंबे समय तक, बिना किसी वजह के मंजूरी नहीं दिये जाने के मामलों में न्यायालय विधेयक की प्राथमिकता की जांच किए बिना एक निश्चित अवधि में फैसला करने का निर्देश देते हुए एक सीमित परमादेश रिट जारी कर सकते हैं।

थरूर ने अपनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक्स पर एक पोस्ट में थरूर ने प्रधानमंत्री के मंगलवार के भाषण की तारीफ करते हुए लिखा कि “यह आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रेरणा, दोनों का मिश्रण था, जो राष्ट्र को प्रगति के लिए बेचैन रहने का आ न करता है।” यह प्रशंसा सामान्य लग सकती थी, अगर प्रधानमंत्री ने उसी भाषण में यह बात भी न कही होती कि “10-15 साल पहले कांग्रेस में घुसे शहरी नक्सल और माओवादी ताकतों ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बना दिया था, जिसने अब राष्ट्रीय हितों को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए देश के हितों को छोड़ दिया है।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा: “आज माओवादी मुस्लिम कांग्रेस देश की एकता के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है।” कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने थरूर की टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण में कोई प्रशंसीय बात नहीं लगी। कांग्रेस

लेकिन सत्ता में आने के बाद, उन्होंने इसी साधन को और परिष्कृत रूप देकर, इन अवैध प्रवासियों को अपना प्रमुख एवं बड़ा वोट बैंक बना लिया। देशभर की रिपोर्टें बताती हैं कि पकड़े गए अधिकतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के पास पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ इलाकों में बने आधार और वोटर कार्ड पाए जाते हैं। नवीनतम अनौपचारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इन लोगों में डर फैल गया है। न्यू टाउन क्षेत्र, जहाँ पहली बार आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा रहती है, वहाँ बहुत सी झोपड़ियां और कमरे तालाबंद मिले हैं और उनमें रहने वाले लोग वापस बांग्लादेश लौट गए हैं। मुसलमान एसआईआर प्रक्रिया के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं और एक समय ममता ने वादा किया था कि वे इस प्रक्रिया को रोक देंगी। अब वही लोग ममता के खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि वे इसे रोकने में नाकाम रही हैं।

इसी वजह से ममता अब एसआईआर प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकने के नए तरीके खोज रही हैं। हो सकता है कि इस प्रक्रिया को बीच में रोकने के लिए वे किसी बड़े पैमाने की कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी को भी बढ़ावा दे दें।

नीतीश ...

नेता संदीप दीक्षित ने थरूर को पाखंडी बताते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री इतने योग्य लगते हैं, तो वे भाजपा की क्यों नहीं शामिल हो जाते? सी.पी.एम. के सांसद जॉन ब्रिट्टास ने भी थरूर पर जमकर हमला किया। उधर भाजपा इस विवाद का फ़ायदा उठाने में लगी है। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को “ईंदिरा नाज़ी कांग्रेस” कहा और पार्टी पर थरूर के खिलाफ एक और फ़तवा जारी करने का आरोप लगाया।

नीतीश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नड्डा, चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए के कई अन्य शीर्ष नेता उपस्थित थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुमार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

MARUTI SUZUKI

UPGRADE YOUR CELEBRATIONS WITH THE BALENO.

EFFECTIVE PRICE OF ₹ 5.67* LAKH

THE NEW AGE

BALENO

TECH GOES BOLD

OFFER VALID TILL 30TH NOVEMBER

360 VIEW CAMERA

1st in Segment

HEAD UP DISPLAY

6 AIRBAGS AS STANDARD*

IN-BUILT SUZUKI CONNECT

NEXA SAFETY SHIELD

SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY @

WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at

1800-200-[6392]

1800-102-[6392]

*Ex. showroom Price of ₹ 5.98 899 lakh, Consumer Offer (-) ₹ 15 000, Exchange Bonus (-) ₹ 15 000, Rural Offer (-) ₹ 2 100 = ₹ 5.67 lakh. The actual Effective Price mentioned may vary based on the customer's eligibility, profile, and applicable offers at the time of purchase. T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. For details on safety features, refer owner's manual. NEXA dealers exclusively provide all offers, which vary by model and variant and city. Offers are subject to availability of stock.

*Offer valid on Baleno SIGMA VARIANT till 30th Nov 2025. Not valid on CNG variants. Maruti Suzuki may withdraw offers without notice. Features and accessories shown can vary by variant. *3 years or 1 00 000 km, whichever is earlier. Finance is at the sole discretion of financier and subject to customer profile.